पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री जनपद मेरठ में आयोजित पूर्व–सैनिक पुनर्मिलन समारोह में सम्मिलित हुए

मेरठ की क्रान्ति धरा से वीर सैनिक परिवारों के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की

उ0प्र0 के वीरता पदक विजेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी, दोनों को दोगुना किया जाएगा

पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को सम्पत्ति के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख रु0 से बढ़ाकर 50 लाख रु0 की जाएगी

शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में ही सरकारी सेवा में नियोजित करने की व्यवस्था की जाएगी

मुख्यमंत्री ने 08 जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों तथा विश्राम गृहों का लोकार्पण किया, अमर बलिदानियों की वीर नारियों, माताओं और वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया

वर्दीधारियों का सम्मान डबल इंजन सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से वीर नारियों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी

सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, उसकी वर्दी बदलती, लेकिन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता

मुख्यमंत्री ने मां भारती के वीर सपूतों और उनके परिवारों के त्याग, बलिदान एवं समर्पण को नमन किया

अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रु0 की सहायता दी गयी

शहीदों की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए प्रदेश में वीरगति प्राप्त सैनिकों के नाम पर 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित, 31 विद्यालयों, 48 सड़कों और 03 स्टेडियमों का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाई, किरकी और मोहाली के पैराप्लेजिक केन्द्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के शत–प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर 1.50 लाख रु0 की गई

वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं में 96 करोड़ 78 लाख रु0 की सहायता दी गई

सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रु0 वितरित

जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रु0 उपलब्ध कराए गये, 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए

विकसित भारत का रास्ता विकसित उ0प्र0 से होकर जाएगा,
इस यात्रा में पूर्व सैनिकों का सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण

उ0प्र0 वीरों की भूमि, 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, 2,000 से अधिक जवानों ने अपने शौर्य से पदक अर्जित किए

मेरठ आज अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने चार दशक से लम्बित 'वन रैंक–वन पेंशन' की मांग पूरी

उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर के माध्यम से देश की रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही

स्वदेशी ए0के0–203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा–370 समाप्त कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत तथा एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की संकल्पना को साकार किया गया

प्रदेश में देशविरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

लखनऊ : 14 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी बदलती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता। सेना से अवकाश ग्रहण करने के बाद जब सैनिक अपने गांव लौटता है, तो वह अपने गांव और समाज का मार्गदर्शक बनता है। उसका अनुभव, अनुशासन और नेतृत्व समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है।

मुख्यमंत्री जी आज जनपद मेरठ में आयोजित पूर्व–सैनिक पुनर्मिलन समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 27 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों तथा विश्राम गृहों का लोकार्पण किया तथा वीर सपूतों के अद्वितिय पराक्रम पर आधारित विशेष पुस्तक 'शौर्यगाथा' का विमोचन किया। उन्होंने अमर बलिदानियों की वीर नारियों, माताओं और वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने मेरठ की क्रान्ति धरा से वीर सैनिक परिवारों के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। पहला उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी, दोनों को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने वर्तमान में दिए जा रहे पुरस्कार और वार्षिकी की राशि का विवरण देते हुए कहा कि परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 03 लाख 12 हजार रुपये वार्षिकी, महावीर चक्र विजेता को 31 लाख रुपये एकमुश्त और 02 लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी, वीर चक्र विजेता को 20 लाख 80 हजार रुपये एकमुश्त और 01 लाख 37 हजार रुपये वार्षिकी,

अशोक चक्र विजेता को 32 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और 01 लाख 50 हजार रुपये वार्षिकी, कीर्ति चक्र विजेता को 19 लाख 50 हजार रुपये एकमुश्त और 01 लाख 30 हजार रुपये वार्षिकी शौर्य चक्र विजेता को 13 लाख रुपये एकमुश्त और 65 हजार रुपये को दोगुना किया जाएगा।

इसी प्रकार सेना मेडल/वायु सेना मेडल विजेता को 01 लाख रुपये एकमुश्त 15 हजार रुपये वार्षिकी सहित अतिरिक्त मेंशन–इन–डिस्पैच में 52 हजार रुपये एकमुश्त और 13 हजार रुपये वार्षिकी, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल में 03 लाख 12 हजार रुपये एकमुश्त और 12 हजार रुपये वार्षिकी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल में 02 लाख 60 हजार रुपये एकमुश्त और 11 हजार रुपये वार्षिकी, युद्ध सेवा मेडल में 83 हजार 200 रुपये एकमुश्त और 10 हजार रुपये वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को सम्पत्ति के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा अब 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। यह सीमा वर्ष 2016–17 में तय की गई थी। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार ने यह निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री जी ने तीसरी घोषणा करते हुए कहा कि शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में ही सरकारी सेवा में नियोजित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से अन्य विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि शहीद परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या उसके निकट के जनपद में रिक्त पद पर तत्काल सेवायोजित किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जवान देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करता है, उसके परिवार की चिंता करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। वर्दीधारियों का सम्मान डबल इंजन सरकार का संकल्प है। वर्ष 2017 से पहले शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 में शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी की गई। शहीदों की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए प्रदेश में वीरगति प्राप्त सैनिकों के नाम पर 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही 31 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियमों का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वीरता पदक इस बात का प्रमाण है कि एक सैनिक ने अपने प्राणों से ऊपर अपने राष्ट्र को रखा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता–पिता को भी प्रदेश सरकार प्रतिमाह पेंशन दे रही है। किरकी और मोहाली के पैराप्लेजिक केन्द्रों में उपचार

करा रहे प्रदेश के शत–प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है।

सेना से लौटने वाला जवान अनुशासन, प्रशिक्षण और नेतृत्व का अनुभव लेकर आता है। इस अनुभव का उपयोग प्रदेश के विकास में किया जाना चाहिए। वर्ष 2021 में समूह 'ख' के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए 05 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। पिछले 03 वर्षों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों, 380 रजिस्ट्री कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पूर्व सैनिकों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार, वन विभाग तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तपकर आने वाले युवा उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की ताकत बनेंगे। वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं में 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अन्तर्गत 8,600 से अधिक बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा अनुदान दिया गया है। 907 बेटियों के विवाह के लिए एक–एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। 269 मेधावी बच्चे एन0डी0ए0, आई0एम0ए0 और अन्य सैन्य अकादमियों में चयनित हुए हैं।

सैन्य अकादमी में चयनित होने वाली बेटी को बेटे की तुलना में तीन गुना यानी 75 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में सैनिक स्कूलों का विस्तार किया गया है। लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय यू0पी0 सैनिक स्कूल ने वर्ष 2018 में पहली बार बालिकाओं के लिए भी अपने द्वार खोले।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को अपने कार्यों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। मेरठ सहित चार जनपदों में पुराने भवनों का जीर्णोद्धार किया गया है। आज इसी मंच से शामली, अमेठी, चन्दौली, औरैया, सन्तकबीरनगर, सोनभद्र, अम्बेडकरनगर और गोरखपुर के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया।

पूर्व सैनिकों को उपचार के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए इस वर्ष 14 जनपदों में ई0सी0एच0एस0 पॉलीक्लिनिक के लिए निःशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने 'शौर्य गाथा' पुस्तक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पुस्तक विद्यालयों और पुस्तकालयों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी अपने नायकों को पहचान सके।

मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की प्रत्येक शिकायत प्राथमिकता पर सुनी जाए और उसका समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सैनिकों को अपने गांव में जमीन से जुड़े कार्यों के लिए तहसील और थाने के चक्कर न काटने पड़ें। इस व्यवस्था में लापरवाही अक्षम्य होगी।

प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प देश के सामने रखा है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। इस यात्रा में पूर्व सैनिकों का सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, प्रशिक्षण और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनका अनुभव प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपील की कि वह अपने गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस की भर्ती के लिए तैयार करें। उन्हें नशे से दूर रहने, अनुशासन के महत्व और राष्ट्रसेवा के प्रति प्रेरित करें। कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता की योजनाओं से जुड़कर वे स्वयं भी रोजगार देने वाले बन सकते हैं। इस दिशा में सरकार उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरठ की पावन धरती सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की साक्षी रही है। यहीं बाबा औघड़नाथ की पवित्र धारा से प्रेरणा लेकर कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प लिया था। उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। प्रदेश में लगभग 20 लाख सैनिकों का विशाल परिवार निवास करता है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें करीब 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। इसी प्रदेश ने नायक जदुनाथ सिंह, गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद, सीतापुर के कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय और बुलन्दशहर के ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव जैसे वीर सपूत दिए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने मां भारती के वीर सपूतों और उनके परिवारों के त्याग, बलिदान एवं समर्पण को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे हजारों परिवार हैं, जिनमें दादा, पिता और आज बेटा–बेटी भी वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बुलन्दशहर और गाजीपुर में यह परम्परा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गाजीपुर का गहमर गांव देश में सर्वाधिक जवान देने वाले गांवों में शामिल है। प्रदेश के 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और 2,000 से अधिक जवानों ने अपने शौर्य से पदक अर्जित किए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी देश और समाज सुरक्षित वातावरण में ही प्रगति कर सकता है। यदि सुरक्षा का माहौल न हो, तो विकास की गति को दुर्गति में बदलते देर नहीं लगती। आज हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं, क्योंकि हमारा जवान सीमा पर जागता है। सियाचिन की बर्फीली चोटियां हों, रेगिस्तान की तपती रेत हो, समुद्र की गहराइयां हों अथवा देश के भीतर आयी कोई आपदा–प्रत्येक मोर्चे पर सबसे पहले हमारा सैनिक खड़ा मिलता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक दशक पहले मेरठ की चर्चा किन परिस्थितियों और कार्यों के लिए होती थी, यह सभी जानते हैं। जिस मेरठ ने आस्था और क्रान्ति को एक धारा में पिरोकर भारत की स्वतंत्रता के लिए नई अलख जगाई थी। एक समय उसकी पहचान वाहन

चोरी, अवैध कटान, अवैध कब्जों और माफिया राज के कारण होने लगी थी। यहां के अन्नदाता किसान गन्ने के भुगतान के लिए परेशान रहते थे। चीनी मिलों के बाहर अपना हक मांगने के लिए एकत्र किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थीं। चीनी मिलों पर ताले लगे रहते थे, खेतों में बिजली और नहरों में पानी नहीं मिलता था। खाद के लिए लम्बी कतारें लगती थीं। किसानों को अपने ही खेतों में जाने में डर लगता था।

आज मेरठ अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यहां का खेल सामग्री उद्योग नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। अन्नदाता किसानों को खेतों में बिजली और नहरों में पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरठ की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नमो भारत आर0आर0टी0एस0 कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे और मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस–वे के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय सेना के मेजर ध्यानचन्द जी ने अपनी हॉकी स्टिक से दुनिया भर में भारत का तिरंगा लहराया और ओलम्पिक स्वर्ण पदक के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाया। उन्हीं के नाम पर मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 'मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' आकार ले चुकी है।

एक समय ऐसा भी था, जब वीर सैनिकों को प्रदेश में अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उस दौर में सैन्य ऑपरेशन पर लगातार सवाल उठाकर वीर सैनिकों की वीरता, पराक्रम और साहस को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवादियों की हेकड़ी निकाल दी गई है। प्रदेश के बच्चों को डिफेन्स क्षेत्र में जाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक स्कूलों के निर्माण की कार्यवाही तेज की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा था। इसके लिए उन्होंने पांच प्रण बताए थे–अपनी विरासत का सम्मान, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों का सम्मान, एकता तथा नागरिक कर्तव्य। इन पांच प्रणों में सैनिकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव भी शामिल है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने चार दशक से लम्बित 'वन रैंक–वन पेंशन' की मांग पूरी की। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया और रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई। राष्ट्रीय स्तर पर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ के पद का सृजन कर तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत सुरक्षा रणनीति को मजबूती दी गई। प्रधानमंत्री जी प्रत्येक वर्ष दीपावली का पर्व सीमा और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच जाकर मनाते हैं। इस वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मनाई।

आज देश से नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद समाप्त हुआ है। सेना को आधुनिक हथियार मिले हैं और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आगे बढ़ा है। वर्ष 2013–14 की तुलना में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये हो गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेन्स कॉरिडोर के माध्यम से देश की रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब लखनऊ में बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। स्वदेशी ए0के0–203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे हैं तथा इसकी फाइनल एसेम्बलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। इसके अतिरिक्त, कानपुर में इसके लिए एम्युनिशन का भी उत्पादन किया जा रहा है।

ए0टी0एस0 देवबन्द से लेकर सीमावर्ती जनपदों तक नए कमाण्ड सेन्टर स्थापित कर राष्ट्रविरोधी ताकतों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों की कमर तोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा–370 समाप्त कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत तथा एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की संकल्पना को साकार किया गया है। बॉर्डर इफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर देश की रक्षा को सुदृढ़ किया गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अब तेजी से विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व सैनिक अनुशासन और अनुभव से समृद्ध राष्ट्र निर्माता हैं। वह सेना के सभी अधिकारियों और जवानों के प्रति प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने वीर नारियों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को विश्वास दिलाया कि वह अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ी है। प्रदेश में देशविरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार का संकल्प है कि सैनिक का सम्मान, वीर नारी का सम्मान, शहीद परिवार का सम्मान और पूर्व सैनिक का स्वाभिमान हर हाल में बना रहे। जिन सैनिकों ने अपने जीवन का सर्वोच्च समय देश की सुरक्षा को दिया है, उनके परिवार, सम्मान और भविष्य की चिंता का दायित्व सरकार पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ निभाएगी।

कार्यक्रम को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सोमेन्द्र तोमर ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर जल शक्ति राज्यमंत्री श्री दिनेश खटीक, जनप्रतिनिधिगण, मध्य कमान के जी0ओ0सी0 इन चीफ ले0 जनरल संजय मित्रा सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक तथा शहीद सैनिकों के परिजन उपस्थित थे।

————————

PN-CM-Meerut Visit-Ex Army Men Reunion-14 November, 2026